सह वीर्यम् करवावहै ॥
LET US COOPERATE

सहविद्या

राजभाषा हिन्दी पत्रिका,

उन्नीसवाँ अंक, वर्ष 2023

वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पुणे

Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

Ministry of Cooperation, Government of India)

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ मार्ग, पुणे 411 007, महाराष्ट्र, भारत

Savitribai Phule Pune University Road, Pune 411007- India

■ E-mail: info@vamnicom.gov.in, hindivamnicom@gmail.com ■ Website: www.vamnicom.gov.in

सहकारी शिक्षण एवम् प्रशिक्षण की आवश्यकता - उद्यमिता के साथ प्रशिक्षण को जोड़ना एवम् युवाओं, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए सहकारिता में अवसर

डॉ. गिरीश माँगलिक *

भारत में सहकारी आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक है। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान रखता है। सहकारी आंदोलन ने न केवल सामाजिक स्तर पर महत्त्वपूर्ण बदलाव किया है बल्कि यह आर्थिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में भी प्रवेश कर चुका है। सहकारी आंदोलन ने लगभग 100 प्रतिशत गांवों और 75 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को आच्छादित कर लिया है। लगभग 6.10 लाख सहकारी समितियां (सभी स्तरों पर) 25 करोड़ से अधिक की सदस्यता के साथ विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही हैं। सहकारी समितियाँ कृषि ऋण वितरण, कृषि आदानों का वितरण, बाजार समर्थन प्रदान करने और अन्य क्षेत्रों जैसे मत्स्य पालन, डेयरी, प्रसंस्करण, उपभोक्ता, विपणन, आवास, चीनी, परिवहन, श्रम आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

सहकारी समितियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभों में से एक हैं और इसका मजबूत, स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी होना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें उत्कृष्ट गुणवत्ता प्रबंधन, प्रौद्योगिकी उन्नयन और लागत प्रभावी उपायों पर जोर देने की आवश्यकता है, जिससे ना केवल उनकी लाभप्रदता बढ़ेगी, वित्तीय संसाधन मजबूत बनेंगे जो सहकारिता की पेशेवर छवि बनाने में सहायक होंगे। सहकारी समितियों के कर्मियों, सदस्यों, निर्वाचित नेताओं की कार्यक्षमता को विकसित और प्रभावी बनाने के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

शिक्षा और प्रशिक्षण सहकारिता के 7 मूल सिद्धांतों में से एक है और निरंतर शिक्षा और प्रशिक्षण सहकारी समितियों की दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रणाली को मानव संसाधनों के विकास के लिए और अधिक प्रभावी बनाने हेतु रणनीति बनाने पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि :

सर्वोत्तम परिणाम लाने और अपने संगठनों की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सहकारी सदस्यों की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित और शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। सुदृढ़ और बेहतर समाज को बढ़ावा देने के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण आवश्यक है। उन देशों में जहां सहकारी आंदोलन मौजूद हैं वहाँ सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण पर विशेष महत्त्व दिया जाता है। सहकारी आंदोलन की सफलता सदस्यों की सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ -साथ व्यापार संचालन के तरीके, तथा सहकारिता के सिद्धांतों के पालन और उनके प्रभावी अनुप्रयोग पर निर्भर करती है। सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण का उपयोग सदस्यों को सहकारी सिद्धांतों और सहकारिता के लाभ के बारे में जागृत करने के लिए किया जाता है। इसलिए, किसी भी सहकारी संगठन के समुचित विकास के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों आवश्यक हैं। सहकारी समितियों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने में सरकार सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक है। सरकारों द्वारा मजबूत सदस्य नियंत्रित सहकारी समितियों के निर्माण, अच्छे नेतृत्व को बढ़ावा देने, मजबूत और प्रभावी सहकारी विकास समर्थन को बढ़ावा देने और सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता है तथा सरकारों द्वारा सहकारी क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्तमान में सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए त्री स्तरीय संरचना क्रियाशील है। राष्ट्रीय स्तर पर वैमनीकॉम द्वारा उच्च अधिकारियों की सहकारी प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है। क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान / सहकारी प्रबंध संस्थान (आरआईसीएम/ आईसीएम) राज्य स्तर पर मध्य स्तरीय अधिकारियों की सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण संबधी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। जिला मुख्यालय स्तर पर कनिष्ठ सहकारी प्रशिक्षण केंद्र (जेटीसी) निम्न स्तरीय अधिकारी एवम् सहकारी सदस्यों एवम् प्रबंध समिति के सदस्यों हेतु सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में क्रियाशील है।

उपरोक्त के अतिरिक्त एनसीसीई, बर्ड लखनऊ, एनसीडीसी(लिनैक), एसीएसटीआई और आरबीआई-कॅब, आदि भी सहकारी समितियों की शिक्षण और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा कर रहें हैं। इन संस्थानों के पास सहकारी कर्मियों को प्रशिक्षित और शिक्षित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध है।

* सह-प्रोफेसर, वैमनीकॉम, पुणे

आवश्यकता है । जहाँ सहकारिता से संबधित विभिन्न डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम चलाए जाए जिसके माध्यम से सहकारी क्षेत्र के लिए कुशल पेशेवर प्रबंधक तैयार करने में सहायता मिलेगी । ऐसे युवा जो सहकारी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है वह सहकारिता से संबंधित योग्यताएँ प्राप्त करने के उपरांत सहकारी उद्यमों में अच्छी नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकेंगे । और सहकारी आंदोलन को जन–जन तक पहुँचाने में सफल होंगे ।

हालाँकि, सहकारी प्रशिक्षण संस्थान कुछ स्तर तक सहकारी क्षेत्र की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करके सहकारी क्षेत्र में लाने के लिए कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया गया है । स्कूल और कॉलेज स्तर पर पढ़ने वाले छात्र सहकारिता के बारे में अनभिज्ञ होते हैं और उन्हें सहकारी समितियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है ।

आत्म अभिव्यक्ति, नेतृत्व और करियर विकल्प के क्षेत्र के रुप में सहकारी समितियों को युवा पीढ़ी के लिए आकर्षक बनाए जाने की आवश्यकता है ।

यह आवश्यक है कि सहकारिता को एक अलग विषय के रूप में पहचान देते हुए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए।

स्कूलों और कॉलेजों में सहकारी शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं:

1. विद्यालय स्तर पर सहकारिता को एक अलग विषय के रुप में शामिल किया जाना चाहिए ।
2. सहकारिता के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए स्कूल स्तर पर प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ।
3. सहकारी विशेषज्ञों को स्कूलों में जाकर सहकारिता को करियर के रुप में अपनाने एवं सहकारी संस्थाओं में रोजगार के विकल्प विषय पर व्याख्यान देना चाहिए ।
4. शिक्षकों को सहकारी समितियों पर छात्रों द्वारा परियोजना कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है ।
5. स्कूल के छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सहकारी समितियों के संवेदीकरण पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है ।

महिलाओं और कमजोर वर्ग का समावेश :

समाज में महिलाओं की स्थिति समाज की प्रगति को दर्शाती है। देश में पुरुष प्रधान समाज के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं सबसे अधिक वंचित रही हैं। विभिन्न सहकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के बावजूद सहकारिता में महिलाओं की भूमिका पुरुषों की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है ।

जहां तक विभिन्न सहकारी क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा का सवाल है, यह देखा गया है कि ऋण और बैंकिंग क्षेत्र पर हमेशा अधिक ध्यान दिया जाता है, जहां महिलाओं और कमजोर वर्ग की भूमिका कुछ हद तक सीमित है । लेकिन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी ग्रामोद्योग, पापड़ उद्योग, आवास, उपभोक्ता, बुनकर समितियां और औद्योगिक उत्पादन समितियां आदि के क्षेत्र में महिलाएं और कमजोर वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । इन क्षेत्रों को अधिक सफल और जीवंत बनाने के लिए प्रशिक्षण और शैक्षिक हस्तक्षेप की अत्यंत आवश्यकता है । सहकारी समितियों में महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग को शामिल करने और उन्हें प्रासंगिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लाने से भारत के समावेशी विकास में काफी मदद मिलेगी । जिससे महिलाओं और कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ।

मजबूत और बेहतर समाज को बढ़ावा देने के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण आवश्यक है । सर्वोत्तम परिणाम लाने और समिति की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए और सहकारी सदस्यों की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित और शिक्षित करना महत्वपूर्ण है । आम तौर पर, सहकारी आंदोलन की सफलता सदस्यों की सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ – साथ व्यापार संचालन के तरीके के रुप में सहकारिता के सिद्धांतों,अभ्यास और तरीकों के अनुप्रयोग पर निर्भर करती है ।

सहकारी समितियों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने में सरकार सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक है । सरकारों को मजबूत सदस्य नियंत्रित सहकारी समितियों के निर्माण, अच्छे नेतृत्व को बढ़ावा देने, सुदृढ़ और प्रभावी सहकारी विकास को समर्थन एवं बढ़ावा देने के साथ–साथ सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए । जिसके लिए विभिन्न सरकारों द्वारा सहकारी क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रावधान को बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है ।

***

राजभाषा हिन्दी का विकास - राष्ट्र का विकास